[Shri Dayanand Sahay]

was established 10 years back with the sole purpose of giving credit to exporters to increase our export and giving credit to exporters on a minimum of 7 to 8 per cent of interest. The Government provided them capital of Rs. 200 crores at 6 per cent and 6 1/2 per cent, but what did they do with the money? 70 per cent of their total operation went in definancing. The balance they deposited with sundry investors, private companies, private banks, and with some money they purchased Government bonds. Therefore, the purpose for which they were given this capital was defeated. They get the money at 6 per cent interest and with that money they buy 14 per cent interest-bearing bonds and then they say they are making profits. So, the purpose is defeated. I just want to give you figures of 31st March, 1990. Their total investment was Rs. 478 crores. Out of this, Rs. 277 crores went in re-financeing, Rs. 121 crores they gave to the private parties as sundry investors and Rs. 78 crores they kept for doing this export business. So, my request, my submission, is that there should be a through probe into the working of this bank. The bank Chairman, who is there for the last 8 years should be removed immediately. If the management is not following the charter of the bank, the bank should be closed. Otherwise, it is becoming a private money lender instead of a bank to promote the export of this country. This is my request and submission.

Pakistani inter services intelligence intentions of sabotage in India

डा० बलदेव प्रकाश : (उत्तर प्रदेश) उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अब यह स्पष्ट हो गया है और सर्व-विदित है कि पाकिस्तान की एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हिंदुस्तान के सभी भागों में सारे देशव्यापी विघटनात्मक कार्यवाइयां करने के लिए योजनाएं बना रही है और उन योजनाओं के नतीजे भी निकलने शुरु हो चुके हैं।

अखबारों में भी इस प्रकार की खबरें छपी हैं और सरकार की रिपोर्टस भी इसी तरह की है और जिन टेरोरिस्ट्स का इंटेरोगेशन हुआ है, उससे भी यह बात स्पष्ट हो चकी है कि पाकिस्तान इस बात पर कटिबद्ध है कि हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता को नष्ट करने के लिए देशव्यापी सेबोटेज या विघटनात्मक कार्यवाइयां करवाई जायें।

इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि तथ्य सामने आये हैं, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात में अहमदाबाद, हरियाणा में जो वाक्यात हुए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की तराई के इलाकों में यानी इतनी इतनी दूर के इलाकों में उन स्थानों पर जहां पर उनके मतलब की आबादी है, वहां पर आतंकवादियों ने अप सैल बना लिये हैं, अपने शरण स्थल बना लिये हैं और वहां पर बैठ कर वह सरकार के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाइयां कर रहे हैं।

पंजाब में पिछले दो दिनों से जो पुलिस कर्मचारियों की निर्मम हत्यायें हो रही हैं, वह भी उसी योजना के अन्तर्गत हो रही हैं, क्योंकि जो स्कीम बनती है, वह पाकिस्तान में बनती है। कभी सरकारी अफसर को मारना है, तो उनको वहीं आदेश आते हैं, कभी पुलिस के कर्मचारियों के परिवारों को मारना है इस लक्ष्य को लेकर कि पुलिस को इनइफैक्टिव बनाया जाये, यह भी वहीं से आदेश आते हैं। कभी राजनीतिक नेताओं की हत्यायें करनी हैं यह योजना भी वहीं से बनती है।

सभी योजनाएं वहीं से बन कर के हमारे यहां आतंकवादियों को दी जाती हैं और वह यहां उनको कार्यन्वित करते हैं। इस विषय में मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम इस समस्या का.–. यह व्यापक धारणा जो है, उसको नहीं समझेंगे, तब बक तम इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

पंजाब में दस-बारह सालों से यह समस्या हो रही है। हम वहां इसको कंटेन नहीं कर सके। वहां से राजस्थान उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह पर फैली है ....

और इतना कुछ होने के बाद भी आतंकवादियों की जो प्रकार शक्ति है, स्ट्राइकिंग पावर है, वह कम नहीं हो सकी है। क्यों कम नहीं हो सकी है कि जितने हथियार हम उनसे छीनते हैं, उतने ही हथियार उनको और वहां से मिलते हैं इसलिये उनकी स्ट्राइकिंग पावर मेंटेंड है, वैसे की वैसे बनी हुई है।

मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं कि 16 तारीख को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सचिवों की कांफ्रेंस हो रही है। हमारी सरकार अगर इस समस्या को इतना गंभीर समझती है, तो क्यों नहीं हम उसमें इस विषय को उठाते ? जब तक पाकिस्तान की सरकार इस बारे में पूरा भरोसा न दिलाए, तब तक इन सम्मेलनों का, इन बैठकों का इन मीटिंग्ज का कोई अर्थ नहीं निकलता। एक तरफ मीटिंग्ज हो रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान हत्याएं करवा रहा है, हिन्दुस्तान को तोड़ने की साजिशें रची जा रही हैं। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार 16 तारीख को मीटिंग का बायकाट करे, अगर पाकिस्तान उस सचिवों की सभा के अन्दर सम्मेलन के अन्दर यह भरोसा न दिलाए। सब से पहले एजेंडा के ऊपर यह सवाल आना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I have to inform hon. Members that the Prime Minister will make a statement in the Rajya Sabha today regarding enhancement of the pension of freedom fighters. The statement will be made at 5.30 p.m.

Health Hazard to residents of Jaitwal Kalan and its sudrounding villages in Sangrur District of Punjab due to pollution

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : (नाम-निर्देशित): मैडम, भोपाल गैस कांड देश एक बार देख चुका है और पंजाब में जैतवाल कलां गांव में एक रालसन कार्बन लिमिटेड नाम की एक फैक्टरी है, जो कार्बन बनाती है। आस-पास के बीसियों गांव में उसका कार्बन फैलता है और इतना कार्बन वह होता है, जैसे कि बादलों की तरह हो। उसने वहां के लोगों की जिन्दगी तहस-नहस कर रखी है। लोगों के चेहरे काले होते हैं, उनके खाने, जो वे बोते हैं, वह काला होता है। जो पशुओं का चारा मिलता है, वह काला होता है। मैं खुद वहां 3 जून को गया हूं। मैंने वहां जाकर देखा कि युकिलिप्टिस के बड़े-बड़े पौध काले हुए हुए है। वहां मिलिट्री के डाक्टर्स की एक टीम आई हुई थी। उन्होंने कुछ लोगों को एग्जामिन किया और उन्होंने कहा कि यह इसी वजह से बीमारियां हैं और उनको सांस की बीमारियां हैं और ऐसी ही बीमारियां आ रहीं हैं। इस दिशा में क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है ? यह मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि सरकार इसके संबंध में सख्त कदम उठाए। कई बार ऐसा हुआ है, उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को और जगह-जगह लोगों ने, वहां की ग्राम-पंचायतों ने रेजोल्यूशन करके दिए हैं कि इसको बन्द किया जाए और हमारी जिन्दगी को बचाया जाय। लेकिन उसका कोई हल नहीं हो रहा है। अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी दी है। लेकिन जब भी कोई अधिकारी वहां देखने जाता है उनका आरोप यह है कि पैसा लेकर उन पर कुछ अमल नहीं किया जाता और फैक्टरी को चलने जाता है। फैक्टरी को उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करने दिया जाता है। अजितवाल कलां, अजितवाल खुर्द, रोडीबाल, बाठ, भोमीवाल, कांनवाल, झुनेर, बौड़ाई मतोई, कूप कलां, कुपखुर्द, दुलवां, बालेवाल, वजीदगढ़ रोहणो आदि ऐसे कई गांव हैं जिन गांवों की पंचायतों ने ये रेजोल्यूशन किये हैं। इसी संबंध में कई बार

उन्होंने इस फैक्टरी का घेराव भी किया है। बजाय इसके कि फैक्टरी को कुछ कहा जाय उन लोगों को दबकाया और डराया जाता है। जिनकी जिन्दगी उस फैक्टरी ने तहस-नहस कर रखी है। उसी फैक्टरी के बिलकुल पास बच्चों का एक मैट्रिक स्कूल है। उस स्कूल में कोई टीचर आने को तैयार नहीं है और जो टीचर वहां पोस्ट किया जाता है वह अपनी ट्रांसफर करवा कर भागता है। कौन ऐसी बुरी जिन्दगी में आए? ऐसे ही उसके पास एक गुरुद्वारा है, उसका भी यही हाल है। तो इस समय मैं आपसे यह कहना मुनासिब समझूंगा कि विश्वास किया जाता है कि मरने के बाद धर्मराज की तरफ से लेखा-जोखा किया जाता है, लेकिन वहां पर लोग कहते हैं कि यहां ही स्वर्ग दिया है और यहां ही नर्क दिया है और वे गांव वाले समझते हैं कि इस नर्क में रह रहे हैं। इसलिए उन लोगों को इस नर्क से छुड़ाया जाए, मेरी तरफ से आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश है। वहां जो भी लोग उसको देखने जाते हैं, अधिकारी चैक करने जाते हैं, वह जो ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं उसके संबंध में भी ध्यान रख कर इस फैक्टरी को बंद करवाया जाए तभी उनकी जिन्दगी ठीक हो सकती है और बचाई जा सकती है। आग कोई ऐसी घटना न हो, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यही चाहूंगा।

Difficulties being faced by people of Udaipur and Banswara Districts of Rajasthan in getting passports issued to team.

श्री रामदास अग्रवाल: (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विशेष उल्लेख के माध्यम से विदेश मंत्रालय का ध्यान पासपोर्ट के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी परसों मैं उदयपुर गया था। वहां बांसवाड़ा और डुंगरपुर आदिवासी/जनजातीय क्षेत्र के कुछ लोग मेरे पास मिलने के लिए आए थे। उन्होंने जो मुझे समाचार दिया, वह थोड़ा अजीब सा लगने वाला समाचार है। वे लोग पासपोर्ट लेने के लिए विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट विभाग में चक्कर लगा रहे हैं। जो लोग खाड़ी खाड़ी युद्ध में वहां से वापस आ गए थे, उनके पासपोर्ट वहां या तो जल गए थे या जल्द बाजी में वहीं रह गए थे। वे सारे के सारे लोग, जिनकी संख्या करीब पांच से सात हजार है और जिन्हें वापस खाड़ी क्षेत्र में जाने के लिए, वहां काम करने के लिए मौका मिल चुका है, वहां वापस जाकर काम करना चाहते हैं। अब उनके सामने समस्या यह हो गई है कि वे पासपोर्ट आफिस जब जाते हैं तो जो फार्म उनको कलेक्टरी में मिल जाते थे, वह अब वहां न मिलकर जयपुर में मिलते हैं। जो फार्म उन्हें कलेक्टरी में, दो रुपए में मिल जाता था, अब वहां पर पांच सौ रुपए पासपोर्ट आफिस में रिश्वत के रूप में देना पड़ता है और आने जाने में समय भी नष्ट करना पड़ता है।

महोदया, दूसरी बात यह है कि वहां कुछ एजेन्ट ऐसे सक्रिय हो गए हैं, जो प्रत्येक पासपोर्ट के ऊपर पांच से दस हजार रुपए इन लोगों से वसूल करके पासपोर्ट दे रहे हैं। उसी के साथ ही एक समस्या और हो गई है कि यदि एजेन्ट की मार्फत पासपोर्ट एप्लाई नहीं करते हैं तो उनको छह-छह महीने का समय पासपोर्ट प्राप्त करने में लगता है।

महोदया, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब वे लोग अपना काम करना चाहते हैं वापस खाड़ी क्षेत्र में जाकर, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं और बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, जब वे अपना व्यवसाय और रोजगार वहां करना चाहते हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना अनुचित है। मैं विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहता हूं कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि फार्म कलेक्टरी उदयपुर में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मिल जाएं और वहीं से उनको 15 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल जाएं ताकि वे लोग खाड़ी क्षेत्र में जाकर अपना रोजगार कर सकें। मैं ऐसा समझता हूं कि यह भ्रष्टाचार को रोकने की तरफ भी एक कदम होगा और जो वहां पर सरकारी अधिकारियों ने, पासपोर्ट विभाग ने जो धांधली मचा रखी है, उसको रोकने में सहायक होगा। यही मेरा सरकार से आग्रह है। मुझे आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।